PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Duniya, New Delhi
Monday, 14th February 2011, Page: 8
Width: 19.56 cms Height: 9.27 cms, Ref: pmin.2011-02-14.36.12

चाहिए सुदृढ़ साइबर सिक्योरिटी

मुकुल व्यास

कमजोर सुरक्षा वाली साइट्स की सूची में सरकार के पुराने रिकॉर्ड रखने वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार के अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार, भारतीय खाद्य निगम और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की साइट्स भी शामिल हैं।

दिसंबर के आरंभ में सीबीआई की साइट पर पाकिस्तानी हैकरों के हमले ने एक बार फिर हमारी साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया है। पिछले कुछ समय से भारत के प्रमुख प्रतिष्ठानों के संवेदनशील कंप्यूटरों और सरकारी साइट्स में सेंध लगाने की कोशिश चल रही है। ये हमले ज्यादातर चीनी और पाकिस्तानी हैकरों द्वारा किए जा रहे हैं। कंप्यूटरों की हैकिंग में कुछ नेताविहीन हैकरों के खुराफाती ग्रुप भी सक्रिय हैं। समुचित सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण सरकार की कई महत्वपूर्ण साइट्स इन हमलों का आसान टार्गेट बनी हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने केंद्र और राज्य सरकारों की 180 वेबसाइट्स की पहचान की है जो साइबर हमलों के आगे बेहद कमजोर हैं क्योंकि इनके पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं। इनमें योजना आयोग, नौसेना, सुप्रीम कोर्ट और मुंबई, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्टों की साइट्स शामिल हैं।

कमजोर सुरक्षा वाली साइट्स की सूची में सरकार के पुराने रिकॉर्ड रखने वाले राष्ट्रीय अभिलेखागार के अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार, भारतीय खाद्य निगम और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की साइट्स भी शामिल हैं। एनआईसी द्वारा इस समय 5,000 से अधिक सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल्स के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की जांच की जा रही है। जिन सरकारी वेबसाइट्स के पास आईटी सिक्यूरिटी ऑडिटर्स का सिक्यूरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें साइट होस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनआईसी द्वारा होस्ट की जाने वाली सभी सरकारी साइट्स के लिए सिक्यूरिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। अपर्याप्त सुरक्षा वाली साइट्स को यथाशीघ्र अपना सुरक्षा ऑडिट पूरा करवाने को कहा गया है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में हैकिंग की बढ़ती घटनाओं के बावजूद कई सरकारी विभाग अपने कंप्यूटरों की सुरक्षा के मामले में लापरवाह रहे हैं। मसलन 3 दिसंबर को तथाकथित पाक साइबर आर्मी के हमले का शिकार होने वाली सीबीआई की वेबसाइट ने 2007 से अपनी सिक्यूरिटी ऑडिट नहीं करवाई थी। सरकार ने तमाम मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से अपनी साइबर सिक्यूरिटी कोटाइट करने और साइट्स की होस्टिंग से पहले नियमित सिक्यूरिटी ऑडिट करवाने के लिए कहा है। 2005 में भारतीय वेबसाइट्स की संख्या 1.7 लाख थी जो बढ़कर अब करीब एक करोड़ हो गई है। अत: सभी सरकारी एजेंसियों के लिए सुरक्षा मार्गनिर्देशों का परिपालन करना और उन पर निगरानी रखना बेहद आवश्यक हो गया है। वेबसाइट्स पर हमलों से निपटने के लिए भारतीय कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एक विस्तृत संकट-प्रबंध तैयार किया है।

Miscellaneous.